



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-15012020-215415
CG-DL-E-15012020-215415

ब्रह्मांदारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]
No. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSAH 20, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

मामला सं. मूल जांच 32/2019

चीन पीआर से सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग मूल जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/36/2019 - डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) के अनुसरण में मै० आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे यहां "आवेदक" भी कहां गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां "संवद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" अथवा विशेष रूप से "पीयूसी" अथवा "संवद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संवद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संवद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग के लिए सामग्री की चोट विषय देश से डंप किए गए आयात के कारण हो रही है और उसने विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है, जो कि देश से निर्यात या निर्यात किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड या सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल है।

4. सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें त्वचा संक्रमण, हड्डी और संयुक्त संक्रमण, श्वसन या साइनस संक्रमण, मूत्र पथ के संक्रमण और कुछ प्रकार के दस्त शामिल हैं। यह एक संक्रामक विरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है, एक टोपोइजोमेरेज़ IV अवरोधक, एक जीवाणुरोधी दवा, एक ईसी 5.99.1.3 [डीएनए टोपोईसोमेरेज़ (एटीपी-हाइड्रोलाइजिंग)] अवरोधक, एक डीएनए संक्षेपण अवरोधक, एक रोगाणुरोधी एजेंट, एक पर्यावरण संदूषक और एक जीनोबायोटिक।

5. विचाराधीन उत्पाद को सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल और इसके लवण (29419030 उप-वर्ग) के नाम से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। कस्टम वर्गीकरण केवल साकेतिक है और जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में जिन विषय वस्तुओं को डंप किया जा रहा है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। तकनीकी विशिष्टताओं के गुणवत्ता कार्यों या डंप किए गए आयातों के अंत-उपयोगों और घरेलू रूप से उत्पादित विषय वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद के तहत कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दो तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापित करने योग्य हैं और इसलिए उन्हें AD नियमों के तहत लेख की तरह माना जाना चाहिए। इसलिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को विषय देश से आयात किए जा रहे विषय वस्तु की तरह माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

7. आवेदन मैं० आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो विषय वस्तु को देश से आयात किया है और न ही संबंधित देश में किसी विषय के निर्यातक या निर्माता या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित है। याचिकाकर्ता मेसर्स गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड के अलावा, विचाराधीन उत्पाद का एक और निर्माता है, जो याचिका का समर्थन भी कर रहा है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकरण संतुष्ट है कि नियमों के नियम 2 (बी) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की ओर से या उसके द्वारा आवेदन किया गया है।

आधार डंपिंग का आधार

8. आवेदक ने दावा किया है कि चाइना पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमों के अनुबंध । के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने नियमों के अनुबंध । के पैरा 7 के तहत विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद, प्रथम दृष्ट्या निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में सामान्य मूल्य के अलावा अन्य विकल्प चीन के लगभग पूरे आयात के बाद से सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभव नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, विधिवत समायोजित किया है, और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए परिवर्धन के बाद किया है।

9. प्राधिकरण ने DGCI & S लेनदेन वार आंकड़ों के अनुसार विषय देश से निर्यात मूल्य की गणना की है। सागर माल ढुलाई, बीमा, बंदरगाह खर्च, बैंक शुल्क और वैट के लिए समायोजन किया गया है।

10. पूर्व कारखाने के स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना की गई है, जो कि प्राइमा केशी विषय देश से विषय वस्तुओं के संबंध में महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन दिखाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि विषय वस्तुओं को भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है विषय देश से निर्यातकों।

चोट और कारण लिंक

11. घरेलू उद्योग को चोट के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में और आयात और घरेलू उद्योग पर मूल्य दबाने वाले प्रभाव के रूप में कथित रूप से डंप आयात की बढ़ती मात्रा के रूप में हुई डंपिंग के परिणामस्वरूप हुई चोट के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि इसका प्रदर्शन उत्पादन, विक्री और मुनाफे में गिरावट, पूंजीगत रोजगार पर वापसी, और नकदी प्रवाह के विषय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप विषय देश से डंप किए गए आयात के परिणामस्वरूप। घरेलू उद्योग को लगी चोटों के पर्याप्त प्राइमरी साक्ष्य हैं जो कि देश से आयात किए गए आयातों को एंटी-डंपिंग जांच के औचित्य को सही ठहराते हैं।

एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत

12. घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत लिखित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, PUC की डंपिंग के बारे में या उससे उत्पन्न होने वाले निर्यात के बारे में। विषय देश, घरेलू उद्योग की चोट और इस तरह के कथित डंपिंग और चोट के बीच कारण, और अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार नियम 5 के नियम 5 के साथ, प्राधिकरण, इसके द्वारा, अस्तित्व, डिग्री और निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू करता है। विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तुओं के संबंध में किसी भी कथित डंपिंग का प्रभाव और एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की चोट को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

विषय देश

13. वर्तमान जांच में विषय देश चीन पीआर है।

जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (इसके बाद POI के रूप में भी संदर्भित) 01 अप्रैल 2018 से 30 जून, 2019 (15 महीने) है। चोट की जांच अवधि अप्रैल 2015-मार्च 2016 अप्रैल 2016-मार्च 2017 अप्रैल 2017-मार्च 2018 और POI की अवधि को कवर करेगी।

प्रक्रिया

15. नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन वर्तमान जांच के लिए किया जाएगा।

जानकारी प्रस्तुत करना

16. भारत में अपने दूतावास के माध्यम से विषय देश और उनकी सरकार में जाने वाले निर्यातकों, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को पीयूसी और घरेलू उद्योग के साथ संबंध रखने के लिए जाना जाता है, उन्हें अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे फॉर्म में सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। और नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित तरीके।

17. कोई भी अन्य इच्छुक पक्ष नीचे दिए गए समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच के लिए अपने सबमिशन को प्रासंगिक बना सकता है। जानकारी / जमा की जा सकती है:

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

18. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर प्राधिकरण तक पहुंच सके। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए कॉल करने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह पहले प्राप्त किया गया माना जाएगा जिस दिन यह नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनियिक प्रतिनिधि। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकरण एंटी-डंपिंग नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है।

20. सभी इच्छुक पक्षों को तत्काल मामले में अपनी रुचि (व्याज की प्रकृति सहित) अंतरंग करने और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं को दर्ज करने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों (जिसमें उससे संबंधित परिशिष्ट/अनुबंध शामिल हो) से यह अपेक्षित है कि वे उस स्थिति में दो अलग-अलग क्षेत्रों में उसे प्रस्तुत करें जब उसके किसी भाग के संबंध में “गोपनीयता” का दावा किया गया हो।

- (i) एक सैट पर गोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) तथा
- (ii) दूसरे सैट पर अगोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित)।

22. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंकित किए गए बिना प्राप्त किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट कॉपी भी प्रत्येक के 4 (चार) सैट में हार्ड कॉपी सहित प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

23. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना निहित होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा अन्य सूचना जो इस प्रकार की सूचना देने वाले के द्वारा गोपनीय के रूप में दावा की गई हो। सूचना के लिए जिसके संबंध में दावा गोपनीय के रूप में किया जाता है, अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया हो, सूचना देने वाले से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ इसके संबंध में भी सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

24. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति हो और अधिमानतः इसे अनुक्रमित किया गया हो अथवा कवर किया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है लेकिन यह उस सूचना पर निर्भर करेगा जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश विस्तृत व्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालाँकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्यक उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।

25. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाले इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

26. उसके सार्वक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के संबंध में सही कारण का उल्लेख किए बिना किये गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

27. संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशेष अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाले सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

29. यदि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2020

Case No. OI - 32/2019

Initiation of Anti-Dumping Original Investigation concerning imports of Ciprofloxacin Hydrochloride from China PR.

F. No. 6/36/2019-DGTR. M/s Aarti Drugs Limited (hereinafter also referred to as “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of “Ciprofloxacin Hydrochloride” (hereinafter also referred to as “subject goods” or specifically as “product under consideration” or “PUC”, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

- The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Product under consideration

- The product under consideration is “Ciprofloxacin Hydrochloride” or “Ciprofloxacin HCL.”
- Ciprofloxacin Hydrochloride is used to treat different types of bacterial infections, including skin infections, bone and joint infections, respiratory or sinus infections, urinary tract infections, and certain types of diarrhea. It acts as anti-infective agent, a topoisomerase IV inhibitor, an antibacterial drug, an EC 5.99.1.3 [DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)] inhibitor, a DNA synthesis inhibitor, an antimicrobial agent, an environmental contaminant and a xenobiotic.
- The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act in the name of ‘Ciprofloxacin HCL and its salts’ (subheading 29419030). The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

Like Article

6. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the AD Rules. Therefore, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry

7. The Application has been filed by M/s Aarti Drugs Ltd. The Applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. There is another producer of the product under consideration, other than the petitioner, i.e., M/s Godavari Drugs Limited, who is also supporting the petition. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made ‘by or on behalf of the domestic industry’ in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of Alleged Dumping

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has requested to determine normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The Authority, after evaluating the options under Para 7 of Annexure I of the Rules, has prima facie concluded that the options other than Constructed Normal Value are not feasible for determination of Normal Value in this case since almost entire imports are from China. Accordingly, the Authority has determined Normal Value on the basis of cost of production in India, duly adjusted, and after additions for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
9. The Authority has computed the export price from subject country as per DGCI&S transaction wise data. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, port expenses, bank charges and VAT.
10. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country, thereby, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal link

11. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of dumped imports from subject country. There is sufficient prima facie evidence of the injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

12. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the PUC originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Country

13. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation

14. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) in the present investigation is 01st April, 2018 to 30th June, 2019 (15 months). The injury investigation period will cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

Procedure

15. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

16. The known exporters in the subject country and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

21. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

22. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

23. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be

confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

27. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

28. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority